



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2018/00156

दर्ज तिथि:-16.07.2018

1. श्रवणकुमार पुत्र गिरधारीलाल के कायम मुकाम  
1/1 ढेलीदेवी पत्नी श्रवण कुमार  
1/2 कैलाश कुमार पुत्र श्रवण कुमार  
1/3 प्रवीण कुमार पुत्र श्रवण कुमार  
1/4 संगीता पुत्री श्रवण कुमार पत्नी हरीश कुमार
2. युगलकिशोर पुत्र गिरधारीलाल  
जाति माहेश्वरी निवासी गुड़ामालानी हाल निवासी बाड़मेर।

.....वादी

**बनाम**

1. तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री भाखराराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:- राज0 पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-29.09.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है:-

- कि वादीगण के पिता मुतवफी गिरधारीलाल को दिनांक 09.06.1976 को सीलिंग भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा आराजी खसरा संख्या 1578/2 रकबा 28 बीघा मौजा गुड़ामालानी भूमि आवंटित की गई थी।
- कि उक्त आवंटन आदेश की पालना में नांमांतरकरण संख्या 662 दिनांक 16.09.1977 को पारित कर वादीगण के पिता गिरधारीलाल का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
- कि उक्त नई तहसील गुड़ामालानी बनने एवं नवीन राजस्व ग्राम कांधी की ढाणी बनने से उक्त आराजी के हाल खसरा संख्या 1578/2 से 1578/2/1



एवं नवीनतम खसरा संख्या 1656/1578 रकबा 28 बीघा मौजा कांधी की ढाणी दर्ज रिकॉर्ड है।

- कि वादीगण के पिता मुतवफी गिरधारीलाल की मृत्यु के पश्चात् जरिये नामांतरकरण संख्या 83 वादीगण की माता गवरीदेवी का नाम संयुक्त गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि के दौरान वादीगण की माता का देहांत होने एवं वादीगण की माता का फौतगी नामांतरकरण हल्का पटवारी द्वारा नहीं भरने से वादीगण स्व. गवरी के विधिक वारिसान है।
  - कि मुतनाजा अराजी पर वादीगण का कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है।
  - इस प्रकार वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1656/1578 रकबा 28 बीघा मौजा कांधी की ढाणी भूमि पर गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। साथ ही वादीगण का मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1656/1578 रकबा 28 बीघा मौजा कांधी की ढाणी भूमि पर वक्त आवंटन से अधिक समय से शांतिपूर्वक, निर्विरोध कब्जा चला आ रहा है। इस आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 (1) (4) तथा परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-27 के तहत प्रतिवादीगण के उक्त आराजी से अधिकार निर्वापित हो गए हैं तथा वादीगण खातेदार कृषक हो गए हैं।
  - अतः उक्त आधारों पर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1656/1578 रकबा 28 बीघा मौजा कांधी की ढाणी भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी वादीगण को वर्ष 1976 में आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित भूमि लूणी नदी के किनारे पर अवस्थित थी। सन् 1979 सम्बन्त 2036 में लूणी नदी में बाढ आ जाने से उक्त आवंटित भूमि लूणी नदी में समाहित हो गई थी। जिससे यह भूमि काबिल काश्त नहीं रही। वर्तमान में भी उक्त भूमि लूणी नदी के मुख्य मार्ग में अवस्थित है। जिस पर पिछले कुछ वर्षों से लूणी नदी का पानी वर्षा ऋतु में प्रवाहित होता रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि काश्त के काबिल नहीं है। सम्बन्त 2036 के गिरदावरी रिकॉर्ड से आज तक की खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड के अनुसार कभी भी काश्त नहीं की गई है। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर आदिनांक तक काश्त नहीं करने, मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने तथा आवंटित भूमि काबिल काश्त नहीं होने वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं होने, मुतनाजा आराजी का लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में होने एवं मौके पर मेड़, सीमा चिन्ह आदि नहीं होने के आधार पर वादीगण को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।
3. प्रकरण में तनकियात कायम किए गए। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकियात कायम किये गये:-

1. आया वादीगण वैध आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1976 तथा आवंटन के पश्चात खातेदारी शर्तों की पालना किये जाने आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादीगण वैध आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1976 तथा आवंटन के पश्चात खातेदारी शर्तों की पालना किये जाने आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

3. आया वादी को आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-16 के तहत प्रतिबंधित होने तथा आवंटन के पश्चात खातेदारी शर्तों की पालना नहीं किये जाने आधार पर वादी का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रकरण नहीं बनने के कारण दावा वादी काबिल-ए-खारिज है।

.....प्रतिवादी

4. अन्य दादरसी

.....उभय-पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए-

दस्तावेज	संवत् / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खसरा संख्या 1656 / 1578 मौजा कांधी की ढाणी सम्वत् 2071-2074	प्रदर्श-पी01
नक्शा	खसरा संख्या 1556 / 1578	प्रदर्श-पी02
-	खतौनी बंदोबस्त खसरा संख्या 1578	प्रदर्श-पी03
आवंटन आदेश	आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1976	प्रदर्श-पी04
-	आवंटन आदेश की सनद	प्रदर्श-पी05
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 662	प्रदर्श-पी06
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 83	प्रदर्श-पी07
-	नोटिस धारा-80 सीपीसी	प्रदर्श-पी08
-	मृत्यु प्रमाण पत्र गवरी देवी	प्रदर्श-पी09
-	नोटिस की रजिस्टर्ड रसीदें	प्रदर्श-पी10

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

नाम	जाति	निवासी	गवाह
श्रवण कुमार पुत्र गिरधारीलाल	माहेश्वरी	बाड़मेर	पी0डब्ल्यू-1
भंवरसिंह पुत्र आसुसिंह	राजपूत	कांधी की ढाणी	पी0डब्ल्यू-2

6. प्रकरण में श्रवण कुमार पुत्र गिरधारीलाल पी0डब्ल्यू-01 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर निम्न प्रकार कथन किये-

- मेरे पिता को 09.06.1976 को ग्राम गुड़ामालानी के खसरा नं. 1578/2 में 28 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसका नामान्तरण संख्या 662 ग्राम गुड़ामालानी, मेरे पिताजी के नाम पारित होने से मेरे पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई थी उसके बाद कांधी की ढाणी नया गांव बनने पर मेरे खसरा नं. 1656/1578 रकबा मेरे पिताजी गिरधारी लाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुआ। मेरे पिताजी की मृत्यु होने पर यह खेत मेरी माता गंवरी देवी एवं दोनों भाईयों श्रवण कुमार एवं युगल किशोर के जरिये नामांतरण संख्या 83 ग्राम कांधी की ढाणी तारीख 03.08.1997 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। इस दौरान मेरी माता का देहान्त होने से उसकी मृत्यु का नामांतरण करण नहीं भरा गया परंतु गंवरी देवी के जाहिंदा पुत्र हम दोनों भाई है। हमने राजस्व अधिकारियों से खातेदारी अधिकार में नाम दर्ज करने का निवेदन किया परंतु जमाबंदी में हमारे नाम गैरखातेदारी में दर्ज है इसलिए हमने खातेदारी दर्ज करने के लिए दावा पेश किया है। वक्त आवंटन से आज तक आवंटन सुदा भूमि पर कब्जाकास्त हम वादीगण का ही है। वाद के समर्थन में दस्तावेजी सबुत जिसमें जमाबंदी 71 से 74 ग्राम कांधी की ढाणी खसरा नं. 1656/1578, प्रदर्श-01, नक्शा खसरा नं. 1556/1578 प्रदर्श-02, खतौनी बंदाबस्त खसरा नं. 1578 ग्राम गुड़ाखास प्रदर्श-03, आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1976 जिसके क्र.सं. 09 पर मेरे पिताजी को 28 बीघा प्रदर्श-04 है। आवंटन आदेश की सनद प्रदर्श-05 है। नामान्तरण करण सं. 662 ग्राम गुड़ामालानी दिनांक 16.09.1977 के क्र.सं. 04 पर मेरे पिताजी के नाम पारित किया जो प्रदर्श-06 है। नामान्तरण करण सं. 83 ग्राम कांधी की ढाणी मेरे पिताजी की फोतगी का हम दानों भाई व माता के नाम 03.08.1957 भरा गया है जा प्रदर्श 07 है। हमने खातेदारी दर्ज करने हेतु धारा 80 सीपीसी उका नोटिस दिया जो प्रदर्श-08 है एवं मेरी माता गंवरी देवी की मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-09 है तथा नोटिस रजिस्टर्ड की रसीदें प्रदर्श-10 एवं 11 है।

7. प्रकरण में भंवरसिंह पुत्र आसुसिंह पी.डब्ल्यू0-2 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर निम्न प्रकार कथन किये-

- कि मैं श्रवण कुमार व युगलकिशोर पुत्र गिरधारीलाल को पहचानता हूं। जो मेरे सेढा पड़ोसी हैं। गिरधारीलाल को सन 1976 में खसरा संख्या 1578/2 में 28 बीघा भूमि गांव गुड़ामालानी की सरहद में आवंटन हुई थी। गिरधारीलाल का देहांत 30-31 वर्ष पूर्व हो गया और गुड़ामालानी से राजस्व ग्राम कांधी की ढाणी नया बनने पर यह खेत कांधी की ढाणी की सरहद में आ गया है। गिरधारीलाल की मृत्यु बाद इस खेत पर कब्जा काश्त गिरधारीलाल के दोनों श्रवणकुमार व युगलकिशोर का चलता आ रहा है। इस खेत में दोनों भाईयों की रहवास के लिये पुरानी सान व पडवा बना हुआ है। मुझे जब से याद आता है तब से आज तक इस खेत पर कब्जा व काश्त गिरधारीलाल के बाद उसके दोनों पुत्रों का बहैसियत खातेदार कृषक के रूप में देखता आ रहा हूं। इस खेत की श्रावणु फसल एवं नदी आने पर सहवज की खेती के रूप में गेहूं कि व अन्य फसल बोते हैं।

8. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1656/1578 रकबा 28 बीघा मौजा कांधी की ढाणी की भूमि पर वक्त बंदोबस्त से काबिज काशत होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। साथ ही वादीगण का मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1656/1578 रकबा 28 बीघा मौजा कांधी की ढाणी पर वक्त आवंटन से शांतिपूर्वक, निर्विरोध कब्जा चला आ रहा है। इस आधार पर राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 (1) (4) तथा परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-27 के तहत प्रतिवादीगण के उक्त आराजी से अधिकार निर्वापित हो गए हैं तथा वादीगण खातेदार कृषक घोषित किया जाने का निवेदन किया।

9. मैंने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैं:-

1. आया वादीगण वैध आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1976 तथा आवंटन के पश्चात खातेदारी शर्तों की पालना किये जाने आधार पर राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादीगण

10. प्रकरण में प्रथम तनकी राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 से संबंधित है। इस कारण प्रकरण में राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

**15. Khatedar tenants—** (1) *Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*

*Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*

*(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act*

*by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.*

*(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatadari right under sub-section (1) in the land held by him.*

*(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:*

*(a) that the land held by him was let out to him after the commencement of this Act.*

*(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).*

*(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.*

*(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).*

*(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application, declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (1).*

11. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-101 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार भूमि आवंटन के धारक को नियमानुसार शर्तों की पूर्ति किये जाने पर खातेदार घोषित किये जाने के प्रावधान हैं।
12. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-1 जमाबंदी खसरा संख्या 1656 / 1578 रकबा 28 बीघा मौजा कांधी की ढाणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी वादीगण के नाम गैर-खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-101 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार भूमि आवंटन के धारक को नियमानुसार शर्तों की पूर्ति किये जाने पर खातेदार घोषित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात होता है कि पत्रावली के प्रदर्श-04 व 05 के अनुसार वादी को भूमि का आवंटन किया गया है। साथ ही प्रदर्श-06 व 07 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-101 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार भूमि आवंटन किया गया है।

13. परंतु प्रकरण में उल्लेखनीय है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवंटित आराजी लूणी नदी के बहाव क्षेत्र के मध्य में अवस्थित है। साथ ही वादी द्वारा उक्त आराजी पर काश्त के संबंध में कोई खसरा गिरदावरी व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। इससे प्रतीत होता है कि वादी की गैर-खातेदारी आराजी लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण काबिल-काश्त नहीं है। उक्त आराजी लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-16 के तहत तथा राजस्थान भू-राजस्व (अनाधिवासित राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम-1970 के नियम-04 के तहत किसी व्यक्ति को आवंटन हेतु प्रतिबंधित होकर खातेदारी अधिकार प्रौढभूत होने हेतु प्रतिबंधित है। इसी कारण वक्त आवंटन से आदिनांक तक वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सके हैं।
14. इस प्रकार उक्त आराजी लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-16 के तहत तथा राजस्थान भू-राजस्व (अनाधिवासित राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम-1970 के नियम-04 के तहत किसी व्यक्ति को आवंटन हेतु प्रतिबंधित होकर खातेदारी अधिकार प्रौढभूत होने हेतु प्रतिबंधित है। अतः वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के तहत अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहे हैं।
15. प्रकरण में वादीगण द्वारा अभिकथन किया गया है कि वादीगण का मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1656 / 1578 रकबा 28 बीघा मौजा कांधी की ढाणी पर वक्त आवंटन समय से शांतिपूर्वक, निर्विरोध कब्जा चला आ रहा है। इस आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 (1) (4) तथा परिसीमा अधिनियम-1963 की धारा-27 के तहत प्रतिवादीगण के उक्त आराजी से अधिकार निर्वापित हो गए हैं तथा वादीगण खातेदार कृषक हो गए हैं।
16. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। इस संबंध में प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-
- 63. Tenancy when extinguished— (1) The interest of tenant in his holding or a part thereof as the case may be, shall be extinguished*
- (i) When he dies leaving no heir entitled to merit in accordance with the provisions of this Act:*
- (ii) when he surrenders or abandons it in accordance with the provisions of this Act or Rajasthan land revenue Act:*
- (iii) when his land has been acquired under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act No. 1 of 1894)*
- (iv) when he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation:*
- (v) when he has been ejected therefrom in accordance with the provisions of this Act.*
- (vi) when he acquires or succeeds to all the rights therein of a*

*landholder or the landholder inherits or otherwise acquires the same.*

*(vii) when he sells or makes a gift thereof in accordance with the provisions of this Act. or*

*(viii) if he migrates from India to a foreign -country without obtaining a valid passport or without lawful authority:*

*(ix) if the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of they Rajasthan Land Revenue-Act 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956) or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force.*

*Explanation-For the purpose of clause (viii) a tenant who moves or enters into a foreign country without obtaining a valid passport under the India Passport Act. 1920 (Central Act No. 34 of 1920) or without a lawful authority shall be presumed to have migrated from India to a foreign country.*

*(2) The extinction of the interest of a tenant shall operate to extinguish the interest of any sub-tenant holding under him :*

*Provided that in every case not being a case specified in clause (iii) of sub-section (1) such -sub-section shall unless he himself has also been ejected or has become or is liable to ejection under any provision of this Act or any other law for the time being in force or unless he shall have been admitted to his holding otherwise than in accordance with law. have the right to apply for the acquisition of his right of his tenant-in-chief in such holding and in the improvements therein on payment of compensation determinable in accordance-with sections 23, 24 and 25.*

17. इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में वादी द्वारा कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जा/एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्ती हेतु अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-88 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 के तहत निवेदित किया गया है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा छोटू बनाम छीतर व गोपाल बनाम श्रावणी अपील में दिनांक 12.11.2013 को दिये गये निर्णय तथा सरजू राव बनाम अमृत लाल प्रकरण संख्या-2002/5176 अपील में दिनांक 30.08.2018 को दिये गये निर्णय में विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मिलने का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं। अतः प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:-

*60. After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatadari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possession. It is creating a lot of chaos and confusion among the litigants as well as the administrative machinery. This omission in the land laws has also become a cause of multiplicity of litigation. Therefore, we would like to recommend the State of Rajasthan through Chief Secretary for*

*39 making suitable changes in the land laws of the State so as to abolish the law of adverse possession in its entirety and in the alternate to make a clarification for vesting of khatedari rights of the lands, which have been acquired through adverse possession.*

18. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के आधार पर विपरीत कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-63 के तहत स्वामित्व/खातेदारी अधिकार नहीं मिलने के न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर भी वादी को उक्त आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहा प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

*39. In the light of the aforesaid discussion, when we consider the decision in Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala & Anr., (2014) 1 SCC 669 decided by two Judge Bench wherein a question arose whether the plaintiff is in adverse possession of the suit land this Court referred to the Punjab & Haryana High Court decision on Gurdwara Sahib Sannauli v. State of Punjab (2009) 154 PLR 756 and observed that there cannot be 'any quarrel' to the extent that the judgments of courts below are correct and without any blemish. Even if the plaintiff is found to be in adverse possession, it cannot seek a declaration to the effect that such adverse possession has matured into ownership. The discussion made is confined to para 8 only. The same is extracted hereunder:*

*"4. In so far as the first issue is concerned, it was decided in favour of the plaintiff returning the findings that the appellant was in adverse possession of the suit property since 13.4.1952 as this fact had been proved by a plethora of documentary evidence produced by the appellant. However, while deciding the second issue, the court opined that no declaration can be sought on the basis of adverse possession inasmuch as adverse possession can be used as a shield and not as a sword. The learned Civil Judge relied upon the judgment of the Punjab and Haryana High Court in Gurdwara Sahib Sannauli v. State of Punjab (2009) 154 PLR 756 and thus, decided the issue against the plaintiff. Issue 3 was also, in the same vein, decided against the appellant.*

19. इस प्रकार उपरोक्त विधि प्रावधानो एवं न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ में केवल कब्जा मुखालफाना/विपरीत कब्जे के आधार पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में भी केवल कब्जा मुखालफाना/विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण तनकी संख्या-01 वादी के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।

20. अब प्रकरण में द्वितीय तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय तनकी निम्न प्रकार हैं:-

2. आया वादीगण खसरा संख्या 603 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा मौजा लूणवा जागीर में से दावा के संलग्न परिशिष्ट अ में प्रदर्शित 01 बीघा भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादीगण

21. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**188. Injunction against wrongful ejection—**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

22. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारी की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

23. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के तहत केवल खातेदार ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 603 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा मौजा लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड नहीं है। साथ ही तनकी संख्या-01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार नहीं होने से वादीगण के कोई खातेदारी अधिकार घोषित नहीं होते हैं। इस आधार पर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 603 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा मौजा लुणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित नहीं होता है। उक्त आधारों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित नहीं करती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या-02 को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या-02 वादी के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।
24. प्रकरण में तनकी संख्या-03 तनकी संख्या-01 के खण्डन स्वरूप बनाई गई तनकी है। अतः तनकी संख्या-01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार नहीं होने से तृतीय तनकी पर पृथक से विश्लेषण अपेक्षित नहीं है।
25. अतः उक्त आराजी लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-16 के तहत तथा राजस्थान भू-राजस्व (अनाधिवासित राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम-1970 के नियम-04 के तहत किसी व्यक्ति को आवंटन हेतु प्रतिबंधित होकर खातेदारी अधिकार प्रौढभूत होने हेतु प्रतिबंधित है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में भी केवल कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कोई प्रावधान नहीं है। अतः

आदेश है कि

**वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।**

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2018/00156

दर्ज तिथि:-16.07.2018

1. श्रवणकुमार पुत्र गिरधारीलाल के कायम मुकाम  
1/1 ढेलीदेवी पत्नी श्रवण कुमार  
1/2 कैलाश कुमार पुत्र श्रवण कुमार  
1/3 प्रवीण कुमार पुत्र श्रवण कुमार  
1/4 संगीता पुत्री श्रवण कुमार पत्नी हरीश कुमार
2. युगलकिशोर पुत्र गिरधारीलाल  
जाति माहेश्वरी निवासी गुडामालानी हाल निवासी बाड़मेर।

.....वादी

**बनाम**

1. तहसीलदार गुडामालानी।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री भाखराराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:- राज0 पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

**-:पर्चा डिक्री:-**

**वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।**

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर

गुडामालानी-बाड़मेर